POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983)
#ग्रा.ग./2024/अंक 09
मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, पी.एस.ओ., आरएमएस गांधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर 2024
मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में विकसित भारत के निर्माण व चहुंमुखी समृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए, अच्छा-खासा रोडमैप प्रस्तुत किया है। माना जा रहा है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को आत्मनिर्भर व पूरी तरह सम्पन्न देश बनाने की दूरगामी सोच है, जो आगे जाकर एक 'मील का पत्थर' साबित होगी।

बुनियादी ढांचागत विकास को मजबूती देने के लिए देश के जीडीपी की 3.4 फीसदी राशि का आवंटन सराहनीय है। उम्मीद की जा रही है इससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। बजट में हर नागरिक की सेहत का लेखा-जोखा रखने और कृषि क्षेत्र को ग्रोथ का इंजन मानते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक खेती के लिए किसानों की मदद देने जैसी कई घोषणाएं सम्मिलित हैं।

शिक्षा को विश्वस्तरीय, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार-परक बनाने, अनुसंधानों पर विशेष जोर देने, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कर विकास में उनकी साझीदारी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को गारंटी ऋण देकर प्रोत्साहित करने जैसी कई घोषणाएं बजट में शामिल की गई हैं। लेकिन स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के कुल बजट में निवेश बढ़ना चाहिए था, ताकि मानव संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके।

मेरा मानना रहा है, बजट घोषणाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, इस पर नियंत्रण आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर दिया ध्यान

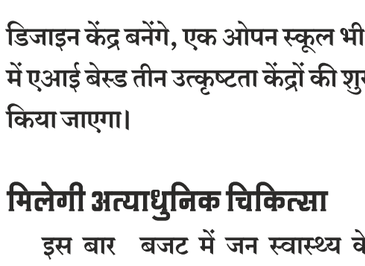

आम बजट में केंद्र सरकार का ध्यान शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर है। युवाओं पर खास नजर रखते हुए इस बार बजट में इन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। देश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा।

एक लाख छात्रों को ब्याज में 3 फीसदी छूट मिलेगी। राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना और 20 नए डिजाइन केंद्र बनेंगे, एक ओपन स्कूल भी खुलेगा। देश में एआई पर भी सरकार का विशेष फोकस है। देश में एआई बेस्ड तीन उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत होगी। इसे 'मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' के तहत शामिल किया जाएगा।

मिलेगी अत्याधुनिक चिकित्सा

इस बार बजट में जन स्वास्थ्य के लिए 90958 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह पिछले बजट की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन इस बार कोई बड़ी योजना नहीं है। इसमें 87 हजार करोड़ रुपए का बजट परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के लिए रखा गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 7300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के लिए 2023-24 में 7200 करोड़ रुपए का प्रावधान था। यानी इस बार मात्र 1.4 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी की गई है। इस बार मुख्य रूप से एक्स-रे ट्यूब जैसे मेडिकल उपकरणों पर टैक्स छूट और 3 कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है।

मेडिकल रिसर्च के लिए बढ़ाया बजट

पिछले बजट में निकलसेल व एनिमिया जैसी बीमारियों का खात्मा करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा गया था। यह जारी रहेगा। आयुष मंत्रालय का बजट इस साल बढ़ाकर 3700 करोड़ रुपए किया गया है।

ऑटोनोमस हेल्थ बॉडीज का बजट इस बार बढ़ाकर 18013 करोड़ किया गया है। एम्स दिल्ली के लिए राशि बढ़ाकर 4728 रुपए की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का बजट भी 2200 से बढ़ाकर 2732 करोड़ रुपए किया गया है।

पांच साल में 4.10 करोड़ को रोजगार

सरकार ने शिक्षा और कौशल के साथ पांच साल में 4.10 करोड़ को रोजगार देने का वादा भी किया है, वहीं पहली बार नौकरी करने वालों को 15 हजार रुपए की मदद भी दी जाएगी। स्टार्टअप योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अब एंजल टैक्स नहीं लगेगा।

देश की शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवा इंटर्नशिप करेंगे। उन्हें इस दौरान पांच हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता और 6 हजार रुपए की एक बार मदद भी दी जाएगी। बजट में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास का वादा किया गया है। इन सबके अलावा भी अनेक सुविधाएं देने के वादे बजट प्रस्तुत करते हुए किए गए हैं।

ग्रामीण विकास को खास अहमियत

इस बार ग्रामीण विकास पर 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

63 हजार गांवों में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा। इससे देश के पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। देश में 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। इस पर 19 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान

आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक दशा में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाए जाएंगे। इस अभियान का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों व आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

इस अभियान के तहत उनके लिए विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आएंगे और इससे पांच करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

शहरों को स्मार्ट बनाने के होंगे काम

शहरों को स्मार्ट बनाने के काम तेजी से होंगे। शहरों में पीएम आवास योजना के तहत पांच साल में एक करोड़ आवास गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

बजट में 100 शहरों में जलापूर्ति सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन पर भी खास ध्यान दिया गया है। राज्यों के विद्युत तंत्र को मजबूती देने के लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लोगों को मदद मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्व-सहायता समूह होंगे लाभान्वित

आपसी साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ-साथ महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देने के काम किए जाएंगे।

ग्रामीण स्तर तक महिला संचालित औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से इनके उत्पादों को बड़े बाजारों तक प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि वह अपने उत्पादों को अच्छे लाभ के साथ विक्रय कर आत्मनिर्भर हो सकें।

कृषि क्षेत्र को माना 'ग्रोथ का इंजन'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को 'ग्रोथ का इंजन' मानते हुए, बजट में कृषि उत्पादकता व किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

दो वर्षों में देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा की गई है, साथ ही जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी है। बजट में बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी विक्रय के लिए किसान-उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को सक्षम बनाने का वादा किया गया है।

गांवों में स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण योजना के लिए 7.19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण रोजगार से जुड़ी मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 86 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

जल जीवन मिशन के बजट में भी इजाफा किया गया है, जिससे घरेलू जल कनेक्शन व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम होगा। इसके साथ ही बजट में गांवों और गरीबों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है।

एमएसएमई उद्योगों को बिना गारंटी ऋण

बजट में वित्त मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र और खासतौर पर छोटे व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को विकास की गारंटी देकर समृद्ध बनाने का भरोसा दिया है। संकटकाल में उद्यमियों को सहायता देने का प्रावधान भी बजट में है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी सहूलियत रहेगी।

एमएसएमई उद्योगों के लिए विशेष पैकेज के तहत वित्त पोषण, विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल किया गया है। तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण खरीद के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। हर आवेदक को 100 करोड़ तक का गारंटी कवर देने के लिए स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी। जबकि ऋण की राशि इससे ज्यादा हो सकती है।

बुनियादी विकास की लम्बी छलांग

बजट में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 11लाख 11हजार 111 करोड़ रुपए का प्रावधान कर विकसित भारत के लक्ष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और सड़क से आसमान तक के विकास को पंख लगेंगे। शहरों से लेकर गांवों तक अच्छी सुविधाएं मिलेंगी।

बजट में 26 हजार करोड़ रुपए सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए निर्धारित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास होगा, गांवों तक सड़कों के माध्यम से आसान पहुंच होगी। नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे। रेल व हवाई यात्रा के साथ ही जल परिवहन को भी खास बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई है।

दलहन और तिलहन में होंगे आत्मनिर्भर

दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाया जाएगा। सरकार इनके उत्पादन और मार्केटिंग को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्योरा रजिस्ट्री में दर्ज होगा।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे लाभार्थी किसानों को साल में 12 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। इनके अलावा भी किसानों के लिए खेती को लाभप्रद बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

विकास में बढ़ेगी महिलाओं की भूमिका

वित्त मंत्री ने विकास में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखकर विभिन्न मंत्रालयों के तहत उनके सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं को और आगे बढ़ाते हुए इस बार बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि आवंटित की है।

यह देखा जा रहा है कि देश में कामकाजी महिलाओं व बालिकाओं की संख्या और उनके काम करने की गति काफी तेजी से बढ़ रही है। नौकरियों के साथ-साथ अन्य रोजगार क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे व शिशुगृहों की स्थापना की जाएगी। सरकार का जोर महिलाओं को विशेष स्किल में प्रशिक्षित करना है।

बजट की अन्य राहतभरी खास घोषणाएं

- नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत देते हुए बजट में न्यू टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन 50000 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए किया गया है। इससे अब 7.75 लाख रुपए तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर राहत दी गई है। (कृपया पूरी जानकारी के लिए आयकर विशेषज्ञ से संपर्क करें)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इसके लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का बजट 177 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1064 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें उज्ज्वला योजना, सौभाग्यम योजना, उजाला योजना, पीएम जनधन योजना आदि के पात्र परिवारों को फायदा मिलेगा।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बजट में 13539 करोड़ रुपए आवंटित किए है। यह पिछले बजट के संशोधित अनुमान से 9853.32 करोड़ रुपए से 37 फीसदी ज्यादा है।

निराली

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'चट्रस' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।
'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485